नईदुनिया

जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप भेजी गई यूएई

नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के जीआई-टैग प्राप्त प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को भेजी गई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने इस निर्यात को सुगम बनाया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले जीआई टैग प्राप्त प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम यूएई को निर्यात किया गया है। इसके साथ ही आमों का पहला व्यावसायिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात के लिए शुरू हो गया है।

मंत्रालय ने कहा कि जीआई-टैग वाले प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आमों की एक मीट्रिक टन की पहली कमर्शियल खेप 26 जून को मेसर्स साल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भेजी गई। यह खास खेप रीवा सुंदरजा आम की अंतरराष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत है, उम्मीद है कि इससे आने वाले सीज़न में नियमित निर्यात का रास्ता खुलेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इस व्यावसायिक निर्यात से रीवा इलाके के आम उत्पादकों को काफी आर्थिक फ़ायदा होने की उम्मीद है। जहां स्थानीय बाजार में रीवा के सुंदरजा आम की मौजूदा कीमत लगभग 100 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसको एक्सपोर्टर ने इसे 150 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा। इस तरह 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम का यह अतिरिक्त फ़ायदा सीधे किसानों को मिलता है, जो उत्पादकों को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड वैल्यू चेन से जोड़ने के आर्थिक लाभ को दिखाता है।

मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से रीवा के किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में भारत के खास कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अहम कदम है। इस सफल एक्सपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र-विशेष के कृषि उत्पादों की अलग पहचान बनाने में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) रजिस्ट्रेशन के महत्व को उजागर किया।

न्यूज ब्रीफ

भारत के लग्जरी कार बाजार की रफ्तार थमी, पांच साल की तेजी पर लगा ब्रेक

मुंबई। लग्जरी कार बाजार की पांच साल की शानदार रफ्तार पर 2026 की पहली छमाही में ब्रेक लग गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, रुपये की कमजोरी और लगातार बढ़ती कीमतों के कारण 40 लाख से अधिक कीमत वाली कारों की बिक्री में ठहराव आ गया है। उद्योग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, लग्जरी कारों की बिक्री 24,000 से 25,000 यूनिट के बीच ही सीमित रही। पिछले पांच सालों में लग्जरी कारों की कीमतों में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी और बढ़ी हुई आयात लागत है। इससे प्रीमियम सेगमेंट के वे ग्राहक, जो पहली बार लग्जरी कार खरीदना चाहते थे, अब अपनी खरीदारी टाल रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हाई-नेट-वर्थ निवेशक भी वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए बड़े खर्चों से बच रहे हैं। हालांकि, सबसे महंगी और हाई-एंड अल्ट्रा-लग्जरी कारों की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है, जिस पर वाहन निर्माता कंपनियां अब अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

वैश्विक शांति वार्ता से तेल बाजार को राहत, भारत में ईंधन हो सकता है सस्ता

मुंबई । अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में हुई प्रगति ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को राहत दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस वैश्विक बदलाव से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद जगी है। हालांकि, भारतीय तेल कंपनियों ने 27 जून को जारी अपने नवीनतम दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार घटती कीमतों ने घरेलू उपभोक्ताओं में राहत की आस जगाई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों के कारण यह स्थिरता कब तक बनी रहेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। नए रेट्स के अनुसार, तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने आम जनता पर ईंधन के बढ़ते दामों का भारी बोझ पड़ा था। 25 मई को हुई आखिरी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल करीब 7.50 रुपये और डीजल लगभग 7.60 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया था, जो चार साल बाद दर्ज की गई सबसे बड़ी वृद्धि थी। इसी कड़ी में, सीएनजी और एलपीजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर मार्च से जून 2026 के बीच दो बार बढ़कर 942 रुपये का हो चुका है।

फाक्सकान का भारतीय इकाई में बड़ा निवेश, 99.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली। ताइवान की दिग्गज इलेक्ट्रानिक कंपनी फाक्सकानने अपनी भारतीय सहायक कंपनी, फाक्सकान हान हाई टेक्नालजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 99.9 फीसदी कर दी है। समूह की सहायक कंपनी फाक्सकान सिंगापुर ने 3.72 करोड़ डालर में लगभग 35.173 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिससे भारतीय इकाई में उसकी कुल हिस्सेदारी 2.82 अरब डालर मूल्य के 23.18 अरब शेयर हो गई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, यह कदम ऐसे समय आया है जब फाक्सकान अपनी 3+3+3 रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा और रोबोटिक जैसे उभरते उद्योगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। आईफोन बनाने वाली यह सबसे बड़ी कंपनी भारत में अपने उत्पादन को लगातार बढ़ा रही है। चेन्नई के श्रीपेरुंबुदूर में इसका सबसे बड़ा विनिर्माण आधार है, जहां ऐपल आईफोन की असेंबलिंग की जाती है।

गैर-विनिर्माण खाद्य कारोबारियों को केंद्र से बड़ी राहत : नियमों में हुआ बदलाव , ईज आफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने खाद्य कारोबार क्षेत्र में ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन करते हुए गैर-विनिर्माण खाद्य व्यवसायों को कुछ रिकार्ड रखने और स्टाक रोटेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट- फिफो या फर्स्ट एक्सपायर फस्ट्र आउट - फेफो से जुड़े नियमों से छूट दे दी है। इस बदलाव से विशेषकर छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ काफी कम होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य व्यवसायों पर अनावश्यक नियामक बोझ को कम करना और व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत, अब खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और अन्य गैर-विनिर्माण खाद्य कारोबारियों को फिफो या फेफो सिद्धांतों के आधार पर स्टाक का प्रबंधन करने और उससे संबंधित रिकार्ड रखने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। पहले यह नियम सभी लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों पर लागू था।

सरकार का मानना है कि गैर-विनिर्माण इकाइयों के लिए इन नियमों का पालन करना एक अतिरिक्त बोझ था, जबकि खाद्य सुरक्षा के लिए इसका सीधा प्रभाव सीमित था। हालांकि, खाद्य निर्माण करने वाले कारोबारियों के लिए ये नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। निर्माण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखने और उत्पाद की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए फिफो या फेफो जैसे स्टाक प्रबंधन पद्धतियां आवश्यक मानी गई हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता तक केवल ताज़ा और सुरक्षित उत्पाद ही पहुंचे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला खाद्य क्षेत्र में जोखिम-आधारित और परिणाम-केंद्रित नियामक व्यवस्था को बढ़ावा देने की व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने स्थायी लाइसेंस, टर्नओवर सीमा में संशोधन, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए दोहरे अनुपालन की समाप्ति और जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली जैसे कई नियमों को आसान बनाया है।

ओपन एआई ने भारत के लिए उबर के पूर्व प्रमुख प्रभजीत को एमडी नियुक्त किया

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया में अग्रणी ओपन एआई ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के पूर्व अध्यक्ष प्रभजीत सिंह को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति देश में जनरेटिव एआई की बढ़ती मांग और ओपन एआई की व्यापक उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से की गई है, जिससे भारत में एआई इकोसिस्टम को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रभजीत सिंह सितंबर से भारत के एमडी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के एमडी किरण मणि को रिपोर्ट करेंगे। भारत में ओपनएआइ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर, वे उपभोक्ता सेवाओं के विस्तार, एंटरप्राइज अपनाने, रणनीतिक साझेदारियों, नियामक मामलों और संचालन की देखरेख करेंगे। सिंह उबर के साथ लगभग 11 वर्षों तक जुड़े रहे, जहां उन्होंने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में कंपनी के मोबिलिटी कारोबार का नेतृत्व किया। आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद से शिक्षित सिंह का तकनीक, रणनीति और बिजनेस डेवलपमेंट का व्यापक अनुभव ओपन एआई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एआई बाजारों में से एक मानते हुए ओपनएआई इस नियुक्ति के जरिए देश में अपनी पैठ बढ़ाने और नवाचार को गति देने का लक्ष्य बना रही है ।

इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाया दम, निवेशकों में लौटी खुशी

मुंबई

पिछले हफ्ते मोहर्रम की छुट्टी के कारण भारतीय शेयर बाजार में केवल चार कारोबारी सत्र रहे, जो उतार-चढ़ाव से भरे रहे। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को शानदार उछाल के साथ हुई, निवेशकों के लिए खुशियां लेकर आई। हालांकि, मंगलवार को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे शुरुआती बढ़त बेअसर हो गई। सप्ताह के मध्य और अंत में मजबूत रिकवरी दर्ज की गई, लेकिन मानसून की धीमी चाल एक चिंता का विषय बनी रही, जिसने निवेशकों और नीति-निर्माताओं के माथे पर लकीरें खींचे रखीं।

सप्ताह का पहला कारोबारी दिन सोमवार शेयर बाजार के लिए एक जोरदार वापसी लेकर आया। सेंसेक्स 423 अंकों की बढ़त के साथ 77,226 पर खुला और दिन के दौरान 77,325 के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया। अंत में, सेंसेक्स 291 अंक और निफ्टी 89 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों को शुक्रवार की गिरावट के बाद बड़ी राहत मिली। हालांकि, यह उत्साह मंगलवार को फीका पड़ गया, जब भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार लाल निशान में फिसला और अंततः सेंसेक्स लगभग 900 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 23,900 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयरों में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया।

धीमी मानसून चाल ने बढ़ाई फिक्र, मंगलवार को बाजार में हुई बड़ी बिकवाली

सप्ताह के मध्य में, भारतीय बाजार ने प्रभावशाली वापसी की। बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर खुले और दिन के कारोबार में सेंसेक्स 900 से अधिक अंकों तक उछल गया, जबकि निफ्टी ने 24,050 का अहम स्तर पार कर लिया। फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर के शेयरों ने इस बुलिश रैली में अहम भूमिका निभाई, जिससे निवेशकों को लगभग दो लाख करोड़ रुपये का फायदा मिला।

गुरुवार को भी यह तेजी बरकरार रही, कच्चे तेल की गिरती कीमतों ने बाजार के सेंटीमेंट को और मजबूत किया। सेंसेक्स 109 अंक चढ़कर और निफ्टी 24,050 के पार बंद हुए। कुल मिलाकर, यह सप्ताह भारतीय बाजार की लचीली प्रकृति को दर्शाता है, लेकिन धीमी मानसून की चाल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है।

श्रीलंका में जाइडस लगाएगी 2 करोड़ डालर का दवा संयंत्र

नई दिल्ली। भारतीय दवा कंपनी जाइडस लाइफसाइंसेज ने श्रीलंका की सनशाइन हेल्थकेयर के साथ मिलकर 2 करोड़ डालर से अधिक के निवेश से एक दवा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य श्रीलंका की दवा आयात पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। दोनों कंपनियों ने जाइडस सनशाइन लाइफसाइंसेज नामक संयुक्त उद्यम बनाया है, जो होराना के निवेश बोर्ड (बीओआई) क्षेत्र में लगभग चार एकड़ भूमि पर इस अत्याधुनिक इकाई को स्थापित करेगा। यह संयंत्र स्थानीय खुदरा बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन कर उनकी उपलब्धता बढ़ाएगा और देश की स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। यह पहल श्रीलंका की हालिया आर्थिक चुनौतियों के बाद स्थानीय विनिर्माण पर जोर देने की नीति के अनुरूप है, जिसने आयात पर निर्भर क्षेत्रों की कमजोरियों को उजागर किया था। इस संयुक्त उद्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और देश की दवा विनिर्माण क्षमताओं के विकास में भी सहायता मिलेगी। इसे जाइडस की विनिर्माण विशेषज्ञता और सनशाइन के मजबूत घरेलू वितरण नेटवर्क का लाभ प्राप्त होगा।

एथेनाल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षित, सरकार ने अफवाहों पर दी सफाई

निराधार दावों और पुरानी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई

नई दिल्ली

भारत सरकार ने एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक और निराधार दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि यह कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से मान्य है और इन दावों का उद्देश्य जनता को भ्रमित करना प्रतीत होता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथेनाल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक आधार पर लागू किया गया है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है।

मंत्रालय ने बताया कि 2003 में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कच्चे तेल के आयात को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह कार्यक्रम, तकनीकी तैयारियों और हितधारकों के परामर्श से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। 2023 से 20 प्रतिशत एथेनाल मिश्रण के कार्यान्वयन के बाद से, इंजन की खराबी या वाहन के टूटने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है।

मंत्रालय ने विशिष्ट दावों का खंडन करते हुए कहा कि ईंधन टैंक में पानी का प्रवेश किसी भी ईंधन के लिए अवांछनीय है और आधुनिक वाहनों में इसे रोकने के लिए डिजाइन संबंधी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाने वाले वीडियो भ्रामक हैं, क्योंकि ईंधन में उपयोग होने वाला एथेनाल औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार होता है और सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन करता है।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने चींटियों वाले वायरल वीडियो पर भी सफाई देते हुए कहा कि ईंधन-ग्रेड एथेनाल में कोई चीनी नहीं होती और इसमें कीट-विकर्षक डिनेचुरेंट्स होते हैं, इसलिए चींटियों के आकर्षण का दावा वैज्ञानिक रूप से निराधार है। इसी प्रकार, वाहन बीमा की वैधता प्रभावित होने के दावों को भी निराधार पाया गया है। मंत्रालय ने दोहराया कि एथेनाल मिश्रण एक विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया है और इसे अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

कोयले से गैस बनाने 37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना शुरू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने घरेलू कोयले से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। हाल ही में जारी अधिसूचना के साथ, इसका लक्ष्य देश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को गति देना है। योजना में प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था होगी, जिसमें कम वित्तीय प्रोत्साहन मांगने वालों को उच्च मूल्यांकन अंक मिलेंगे।

पात्र संयंत्रों और मशीनरी की लागत का 20 फीसदी तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। लाभ के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, मंत्रालय ने सुरक्षा उपाय भी किए हैं; किसी भी परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, किसी कार्पोरेट समूह के लिए 12,000 करोड़ रुपए और अधिकांश डाउनस्ट्रीम उत्पादों (यूरिया/एसएनजी को छोड़कर) के लिए 9,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू कोयले से सिनगैस, मेथनाल, अमोनिया और एसएनजी जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना है। यह योजना लगभग 7.5 करोड़ टन कोयले से गैस बनाने की क्षमता वाली परियोजनाओं को समर्थन देगी, जिससे 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद मिलेगी।

एचडीएफसी बैंक ने मारी बाजी, दूसरों को महंगी पड़ी पूंजी!

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित विशेष स्वैप विंडो सुविधा का लाभ उठाने में अग्रणी रहकर एक महत्वपूर्ण फर्स्ट-मूवर एडवांटेज हासिल किया है। इस सुविधा की घोषणा के तुरंत बाद विदेशी बान्ड बाजार में पूंजी जुटाने वाला यह पहला भारतीय बैंक बन गया, जिसने पिछले हफ्ते 75 करोड़ डालर की पूंजी सफलतापूर्वक और प्रतिस्पर्धी दरों पर जुटाई। हालांकि, इसके बाद आने वाले अन्य भारतीय बैंकों को निवेशकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण ऊंची लागत का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय ऋणदाताओं से बान्ड आपूर्ति में संभावित वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का अग्रणी लाभ एचडीएफसी बैंक ने 5-वर्षीय बान्ड के माध्यम से 75 करोड़ डालर जुटाए, जिसकी प्रभावी ब्याज दर संबंधित अवधि में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से मात्र 90 आधार अंक अधिक थी। 5.067 प्रतिशत की कूपन दर बैंक के डालर बान्ड निर्गमों पर अब तक का सबसे कम स्प्रेड है। आरबीआई द्वारा स्वैप लागत पर सब्सिडी दिए जाने से बैंकों के लिए कोष की लागत में कमी आई, और एचडीएफसी बैंक ने समय पर प्रवेश कर इसका पूरा लाभ उठाया, जिससे उसे अत्यधिक अनुकूल शर्तों पर पूंजी प्राप्त हुई। अन्य बैंकों के लिए बढ़ती लागत एचडीएफसी बैंक की सफलता के बाद, पावर फाइनैंस कारपोरेशन ने भी 5-वर्षीय बान्ड निर्गम के जरिए 30 करोड़ डालर जुटाए, लेकिन उसे संबंधित अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 105 आधार अंक अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ी (प्रभावी ब्याज दर 5.32 फीसदी)। इसी तरह, ऐक्सिस बैंक ने 50 करोड़ डालर से 1 अरब डालर जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन अधिक ब्याज दर के कारण उसे निर्गम का आकार कम करना पड़ा और उसे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 110 आधार अंक अधिक ब्याज दर (5.35 फीसदी) पर पूंजी जुटानी पड़ी। यह स्पष्ट रूप से बाद के निर्गमों के लिए बढ़ी हुई लागत को दर्शाता है। निवेशकों की उम्मीदें और बाजार की चाल बाजार के जानकारों का मानना है कि एचडीएफसी बैंक को पहले बाजार में उतरने का फायदा मिला। इसके बाद के निर्गमों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कम उत्साहजनक रही, क्योंकि वे भारत से आने वाली डालर बान्ड की आपूर्ति का अनुमान जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं।